रणजीत टाइम्स
वर्ष : 1, अंक: 105 इंदौर, गुरुवार 17 अप्रैल 2025
RNI-NO.MPHIN/2015/64585
DIGITAL EDITION

लाड़ली बहनों के खातों में आए 1552 करोड़ रुपए

- सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंडला से जारी की यह राशि
- विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में 1552.38 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री यादव बुधवार को मंडला जिले के टिकरवारा गांव पहुंचे। यहां आयोजित जनकल्याण कार्यक्रम में उन्होंने सिंगल क्लिक से राशि जारी की। योजना के तहत हर हितग्राही को 1250-1250 रुपए की राशि मिली है।

सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56.68 लाख हितग्राहियों को 340.13 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। इससे पहले कार्यक्रम में आए सीएम का मंडला के पारंपरिक शैला नृत्य से स्वागत किया गया। सीएम डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल हुए।

सामूहिक विवाद में 1120 जोड़ों का विवाह गठबंधन में बंधने जा रहे है। सीएम ने सभी नवविवाहित जोड़ों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे पहले मंगलवार की शाम को हल्दी और संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और मंडला विधायक संपतिया उइके ने परंपरागत शैली में जमकर डांस किया। कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी नृत्य में भाग लिया।

देश में बाड़मेर रहा सबसे गर्म श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

- 80 साल का रिकॉर्ड टूटा, 25 राज्यों में आंधी-बारिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौसम विभाग ने बुधवार को देश के 25 राज्यों में आंधी-बारिश का अनुमान लगाया है। बिहार, असम और ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। झारखंड, ओडिशा और मेघालय में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 15 अप्रैल श्रीनगर का बीते 80 सालों में सबसे ज्यादा गर्म दिन था। शहर का तापमान सामान्य से 10.2 डिग्री ज्यादा 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में इस वक्त औसत तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में इससे पहले 20 अप्रैल, 1946 को सबसे ज्यादा तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल को कश्मीर घाटी के अलग-अलग इलाकों में तापमान सामान्य से 8.1 से 11.2 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं, राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा। जिले का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। इधर, हिमाचल में ओलावृष्टि-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां के 4 जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। अगले 5 दिन राज्य में मौसम खराब बना रहेगा। हरियाणा में आज बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। बिहार के 22 जिलों में बारिश-आंधी का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा।

मुजफ्फरपुर में बस्ती में आग, 5 की मौत

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार एक दलित बस्ती के 50 से अधिक घरों में आग लग गई। हादसे में 4 बच्चे समेत 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। वहीं, 15 बच्चे लापता है। मृतकों में छोटू पासवान की बेटी अंशिका कुमारी (05), राज पासवान के बच्चे ब्यूटी कुमारी (08), सृष्टि कुमारी (06), विपुल कुमार (10) शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गोलक पासवान के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते पूरे झुग्गी के इलाके में फैल गई। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया, गांव के गोलक पासवान में घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी।

जेनेटिक काउंसलिंग में समुदाय का सहयोग लिया जाए:राज्यपाल

- समस्त रोगी और वाहकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही लक्ष्य

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में जेनेटिक काउंसलिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक काउंसलिंग कार्य में मध्यस्थों की भूमिका की संभावनाओं पर कार्य करते हुए समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है। रोग को खत्म करने के लिए वैवाहिक और गर्भधारण संबंधी सावधानियां के बारे में सामुदायिक जन जागृति की दिशा में प्रभावी पहल जरूरी है। जेनेटिक काउंसलिंग कार्य में समुदाय के नेतृत्व और पंचायत पदाधिकारियों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि रोगी को स्वस्थ बनाने के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रमाणित औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश के वनों में प्रचुर मात्रा में वन औषधियों की उपलब्धता है। इन औषधियों के सिकल सेल रोगी को स्वस्थ बनाने के अनुभवों और उपयोग के परीक्षणों के प्रमाणीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर तेज गति से किया जाए।

- गुजरात के मोडासा में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

बीजेपी और संघ को हराने का रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है

अहमदाबाद (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा जिले के अरावल्ली पहुंचे हैं। यहां वे सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसके बाद बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी और आरएसएस को हराने के रास्ता गुजरात से होकर जाता है अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा- वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भाजपा-आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा- हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात में ही हुई थी। आपने हमें हमारे महानतम नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए लेकिन हम गुजरात में लंबे समय से हतोत्साहित थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि

कुछ भी मुश्किल नहीं है। पार्टी में बदलाव लाने का फैसला शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी में बदलाव लाने का फैसला किया है। अब जिला स्तर के नेताओं को भी मजबूत किया जाएगा। आज पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो पार्टी के लिए विनाशकारी है। मुझे पार्टी नेताओं से जानकारी मिली है कि स्थानीय चुनावों के टिकट वितरण में स्थानीय लोगों को ही शामिल नहीं किया जाता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा- अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से हुई चर्चा का मुख्य मुद्दा यही था कि राज्य के किसी जिले को अहमदाबाद से नहीं चलाया जाना चाहिए। जिले को जिले से ही चलाया जाना चाहिए। इसके लिए जिला नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी और शक्ति सौंपी जानी चाहिए। हम यह काम अभी से शुरू कर रहे हैं। प्यार से भाजपा के लोगों को बाहर करना है हमें अब नई पीढ़ी को कांग्रेस में लाना है। लेकिन, यह भी ध्यान रखना है कि इस भीड़ में भाजपा से जुड़े लोग भी शामिल होंगे और हमें उन्हें प्यार से बाहर निकालना है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे मजबूत लोग हैं। आपको जहां भी मेरी जरूरत होगी। मैं गुजरात के कोने-कोने में आपके लिए मौजूद रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ना है।

कार्यकर्ताओं से बोलीं माया, विधानसभा चुनाव की तैयारी करिए

लखनऊ (एजेंसी)। मायावती ने बुधवार को बसपा पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता को मेहनत करनी होगी। बसपा का मूल जनाधार दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, जिन्हें भाजपा और कांग्रेस बरगलाने में लगी है। बसपा प्रमुख ने कहा कि समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर वक्त जनता के बीच रहना होगा। उन्होंने संगठन की तैयारियों की समीक्षा कर नेताओं को दिशा-निर्देश दिए। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 300 पदाधिकारी शामिल हुए। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता को बीजेपी-कांग्रेस से दूर रखें।

सिमरोल में बिना अनुमति प्रदर्शन पर दर्ज हुआ मामला, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक दबाव का परिणाम

संवाददाताः विशेष रिपोर्ट

इंदौर-खंडवा रोड स्थित सिमरोल में कांग्रेस नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन बिना प्रशासनिक अनुमति के किया गया, जिसके बाद सिमरोल पुलिस ने एक दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार जिन नेताओं पर मामला दर्ज हुआ है, उनमें प्रमुख नाम शामिल हैं – ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सैनी, राकेश पाटीदार, शेखर मालवीय, अजय, दिनेश सिलवायडिया, नारायण शारदिया, अनिल, कमलेश राठौर, परवेज खान, कैलाश राकेश वर्मा, पंकज देवलाल, रोशन और प्रदेश शारदिया।

कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई भाजपा सरकार के दबाव में की गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सैनी ने बयान जारी करते हुए कहाः "हमने जनता की भलाई और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई। यदि लोकतांत्रिक तरीके से भी आवाज उठाना अपराध है, तो यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है।" पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है और इसी आधार पर FIR दर्ज की गई है।

प्रशासनिक तंत्र बनाम जनआवाज सियासत गरमाई

इस घटना के बाद क्षेत्र में सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस नेताओं ने अगले कुछ दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

इंदौर, हाल ही में अभी दो-चार दिन बीते एक मामला सामने आया जिसमें एक प्रताड़ित महिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है

रंजीत टाइम्स

हम बात कर रहे हैं शबनम बानो महिला की जो रतलाम की रहने वाली है जिनका निकाह इंदौर के खजराना क्षेत्र में सलीम मनिहार युवक के साथ धर्म के अनुसार दान दहेज के साथ संपन्न हुआ था शबनम वानो महिला का कहना है कि मेरी शादी आज से 5 वर्ष पूर्व हुई थी मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोगों की अपनी राजा मंदी से हुई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमें क्या पता था जिनके साथ हमारा निकाह हो रहा है जिनके परिवार में हमारा निकाह किया जा रहा है वह सभी हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करेंगे शबनम बानो ने बताया कि अभी कुछ महीना पहले की बात है कि मेरे पति के द्वारा मुझे मारपीट करके घर से भगा दिया गया हमने अपनी तरफ से कोर्ट में कैस किया है हमने अपने लिए अपने बच्चों के लिए भरण पोषण का पैसा मांगा तो मना किया गया मजबूरी में मुझे कोर्ट में कैस करना पड़ा हमारा 2 महीने से कोर्ट में कैसे चल रहा है लेकिन कुछ दिन पूर्व ही हमारे पास ससुराल तरफ से फोन आने लगे कि हम सभी लोग अपनी जमात को इकठ्ठा करके पंचायत करना चाह रहे हैं शबनम ने बताया हमारी तरफ से मना कर दिया गया कि जब हमारा कोर्ट में कैस चल रहा है तो हम पंचायत में नहीं आना चाहते हैं उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से हमारे पास फोन आया मैसेज आया हमारे समाज का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज रिकॉर्डिंग करके डाला गया और हमारे ऊपर दबाव बनाकर रतलाम से इंदौर बुलाया गया जब हम अपने भाई शकील सादिक ,भांजे वसीम जीजा निजामुद्दीन अपनी बच्ची को लेकर न्याय की गुहार लगाने पंचायत में पंचों के सामने हमारे समाज के सभी लोग शामिल थे हम उनके सामने गए उन लोगों ने बात करने के बहाने अंदर बिठाकर हमारी दो चार बात भी नहीं हो पाई थी कि वह सभी एकत्रित होकर एक साथ हमारे भाई भांजे जीजा सभी को मारने पीटने लगे दौड़ा-दौड़ा कर मरने लगे एक लोगों ने हमारे जीजा के ऊपर शराब की बोतल सर में मार दी जिससे उनको ज्यादा चोट आई है हमारा नाबालिक भांजा उसको भी इन लोगों ने बेरहमी से पिटा जब हम अपनी फरियाद लेकर थाना मल्हारगंज पर पहुंचे तो वहां के थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुशवाह जी ने हमारी तत्काल एफ, आई ,आर लिखवाकर जिन लोगों को चोट आई थी उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा तथा हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपको उचित न्याय मिलेगा शबनम बानो ने कहा कि हमें जिसने बुलाया था उनके साथ जितने भी लोग थे हम मांग करते हैं कि सभी पर सख्त कार्रवाई की जाए।

विधायकों की एक कमेटी करेगी सांची दुग्ध प्लांट का इंस्पेक्शन

- एनडीडीबी और डेयरी फेडरेशन के बीच एमओयू के बाद अब कृषि विकास समिति करेगी दौरे

भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर हुए एमओयू के बीच अब विधानसभा की कृषि विकास समिति भोपाल और इंदौर संभाग का दौरा कर इसके बारे में जानकारी लेगी। कृषि विकास समिति के सभापति और सदस्यों की टीम इस दौरान भोपाल में हबीबगंज भोपाल के सांची दुग्ध संघ के प्लांट और नए लैब का निरीक्षण करेंगे। यहां किसानों से किए जाने वाले दूध के कलेक्शन, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किए जाने और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

विधानसभा की कृषि विकास समिति के सभापति दिलीप सिंह परिहार और उनकी टीम भोपाल और उज्जैन संभाग का दौरा 21 से 23 अप्रैल तक करेगी। समिति का दौरा 21 अप्रैल को एमपी राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के केंद्रीय वीर्य संग्रहण केंद्र करेवा डैम से शुरू होगा। इसके बाद समिति दुग्ध उत्पादन कार्य का अवलोकन और संचालन पद्धति के साथ उसकी प्रोसेस समझेगी। साथ ही फॉर्म पर मौजूद पशुओं की नस्लों और उनकी प्रोडक्टिविटी की जानकारी ली जाएगी। इस दौरान समिति यह जानेगी कि तीन सालों में आय के साधन, व्यय के साथ देसी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण की क्या स्थिति रही है। कृषि विकास समिति मध्यप्रदेश राज्य बीज और फॉर्म विकास निगम में बीज उत्पादन और निगम द्वारा संचालित फॉर्म की तीन सालों की प्रोग्रेस, हानि आदि के बारे में जानकारी लेगी।

ट्रम्प ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ और बढ़ाया, 245 किया

- चीन बोला-ट्रेड वॉर से नहीं डरते,5 दिन पहले अमेरिकी सामानों पर 125 फीसदी टैरिफ लगाया था

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर और आगे बढ़ गया है। अमेरिका ने अब चीन पर 100 फीसदी और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245 फीसदी हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रम्प ने नया टैरिफ लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी। चीन के

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अगर अमेरिका सच में बातचीत को डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है, तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बात करनी चाहिए। लिन जियान ने पत्रकारों से कहा कि 245व अमेरिकी टैरिफ के तहत अलग-अलग टैक्स रेट क्या होगा ये आप अमेरिका से ही पूछिए।

भिक्षा मुक्त इंदौर बनाने का ‘इनाम’ – कर्ज़ और आँसू !

PRAWES भुगतान के लिए सड़क पर, निगम प्रशासन कटघरे में।

इंदौर को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्ति दिलाकर देश में पहला स्थान दिलाने वाली संस्था ‘परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी (PRAWES)’ के सभी कर्मचारियों ने आज नगर निगम मुख्यालय पर अपने दो साल से अधिक समय से लंबित करोड़ों रुपये के भुगतान के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए कर्मचारियों ने निगम प्रशासन की असंवेदनशीलता के खिलाफ नारे लगाए और संस्था की संस्थापक सुश्री रुपाली जैन के नेतृत्व में आयुक्त महोदय से मिलकर अन्याय और अपमान के विरुद्ध लड़ाई और अपने अधिकार की माँग लगाई।

इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाया, बल्कि इस अभियान के तहत 2500 लोगों को पुनर्वासित किया, 228 से अधिक मानसिक रूप से अस्वस्थ और सड़कों पर पड़े लाचार लोगों को रेस्क्यू कर उनका उपचार कराया, सैकड़ों बिछड़े परिवारों को मिलाया, सेकड़ो भिक्षुकों को कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने का भागीरथी प्रयास अभी भी कर रही है। इस कार्य में टीम के सदस्यों पर 72 से अधिक बार जानलेवा हमले भी हुए। आयुक्त महोदय से मुलाकात के दौरान रुपाली जैन ने सीधे सवाल किया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 को समस्त राशि जारी किए जाने के बावजूद भुगतान क्यों नहीं किया गया? इस पर स्थिति तब और बिगड़ गई जब निगम के एक जिम्मेदार उपायुक्त महोदय ने आयुक्त को खुलेआम यह कहकर भ्रमित करने की कोशिश की कि संस्था ने भुगतान हेतु कुछ दस्तावेज ही जमा नहीं किए हैं। आयुक्त महोदय ने रूपाली जेल से कहा कि यदि आप प्रमाण दे देगी तो मैं आज ही आप का पूरा भुगतान करवा दूँगा और अधिकारियों पर कार्रवाई भी करूँगा। संस्था द्वारा तत्काल प्रमाण प्रस्तुत करने पर वे अधिकारी निरुत्तर हो गए। यह घटना निगम में व्याप्त गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों द्वारा वरिष्ठों को गुमराह करने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने रुंधे गले से अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा, “हमने शहर की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर बदले में हमें मिला कर्ज, अपमान और मानसिक प्रताड़ना। बाजार से ब्याज पर पैसा उठाकर हमने काम जारी रखा था, आज वही कर्ज हमें जीने नहीं दे रहा। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।” सुश्री रुपाली जैन ने कहा, “यह केवल भुगतान का मुद्दा नहीं, यह ईमानदारी और विश्वास का गला घोंटने जैसा है। क्या यही इंदौर का मॉडल है, जहाँ अच्छा और प्रामाणिकता से काम करने वालों को दंडित किया जाता है?”

सुश्री जैन ने स्पष्ट किया, “हम पिछले तीन साल से लगातार पत्राचार कर रहे थे, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज हमें सड़क पर उतरना पड़ा। हम तत्काल प्रभाव से अपने संपूर्ण बकाया भुगतान की मांग करते हैं। हम झूठे आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहते हैं। यदि निगम प्रशासन अब भी नहीं चेतता, तो हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे और न्याय के लिए हर संभव कानूनी व लोकतांत्रिक रास्ते अपनाएंगे। हम यह भी मांग करते हैं कि गुमराह करने वाले और बेवजह भुगतान को लंबित रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जांच बिठाकर कार्रवाई की जाए। इंदौर की जनता और मीडिया से अपील की है कि वे इस मुद्दे को सिर्फ एक संस्था की लड़ाई न समझें, बल्कि इसे प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक सरोकारों के प्रति सम्मान की लड़ाई समझकर अपना समर्थन दें।

जिला महिला शसक्तीकरण केंद्र इंदौर द्वारा रहवासियों को जागरूक किए जाने हेतु संवाद का आयोजन

अनिल चौधरी

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रामनिवास बुधौलिया सर के मार्गदर्शन में जिला मिशन समन्वयक DHEW एवं प्रशासक वन स्टॉप सेंटर इंदौर डॉक्टर वंचना सिंह परिहार जी एवं पर्वोलेंटियर वालेंटियर अक्षर सामाजिक सेवा समिति इंदौर दीपमाला यादव द्वारा आज जेल रोड में स्थित आंगनबाड़ी में समस्त महिलाओं साथ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही जोन क्रमांक 3 (शहीद भगत सिंह जोन) में नामांकन के लिए आए समस्त महिला एवं लाभार्थियों एवं रहवासियों के साथ जागरूकता संवाद एवं सामुदायिक संवाद का आयोजन किया गया।जिसमें महिलाओं को 181,1098,112, वन स्टॉप सेंटर,ऊर्जा डेस्क , बाल विवाह निषेध, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला शसक्तीकरण योजना ,DHEW आदि की जानकारी दी गई.।

मुख्यमंत्री से मिले किसान संघ के प्रतिनिधि, जमीन अधिग्रहण के नियमों में बदलाव की रखी मांग, डिफाल्टर किसानों का ब्याज सरकार उठाएगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों को राहत देने की दिशा में एक अहम पहल उस समय देखने को मिली जब भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पारित भू-अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2025 को लेकर अपनी गहरी चिंताओं और आपत्तियों को मुखर रूप से प्रस्तुत किया। किसान संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना किसानों की सलाह और विश्वास में लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना किसानों के हितों के विरुद्ध है और यह स्वीकार्य नहीं होगा। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई अहम मुद्दे उठाए, जिसमें भू-अधिग्रहण के साथ जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, किसानों की भागीदारी और उनके अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को जोरदार तरीके से रेखांकित किया गया। किसान संघ के मुताबिक अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसान को पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए और परियोजना के हर पहलू पर किसान संगठनों से सलाह ली जानी चाहिए। बैठक के दौरान सरकार के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2025 का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया, परंतु किसान संघ इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विस्तार से अपने सुझाव रखे।

किसान संघ की मुख्य मांगों में यह शामिल रहा कि किसी भी विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तभी किया जाए जब किसान की स्पष्ट सहमति हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उस परियोजना की समय सीमा पहले से निर्धारित की जाए और यदि समय पर परियोजना पूरी नहीं होती है तो भूमि को किसान को वापस लौटाया जाए या वर्तमान बाजार मूल्य पर उन्हें मुआवजा दिया जाए। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को विकसित भूमि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा लौटाया जाए, ताकि वे अपनी जीविका जारी रख सकें। छोटे किसानों की सुरक्षा की बात करते हुए किसान संघ ने यह मांग रखी कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है और जिनकी पूरी भूमि परियोजना में अधिग्रहित हो जाती है, उन्हें परियोजना के पूर्ण होने तक भूमि का किराया दिया जाए। जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले भू-अधिग्रहण को लेकर विशेष चिंता जताई गई और किसान संघ ने सरकार से यह आग्रह किया कि ऐसे क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षित रहनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को उनका उचित अधिकार मिले और अधिग्रहीत भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा आवासीय या व्यवसायिक विकास के बाद उन्हीं को लौटाया जाए। किसान संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को चार गुना बाजार मूल्य मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए और उनके परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार उस परियोजना में नौकरी भी मिलनी चाहिए। किसान संघ ने यह भी आपत्ति जताई कि किसानों की भूमि को किसी व्यवसायिक परियोजना में शामिल करके उसे निजी उद्योगों को न सौंपा जाए। उन्होंने यह मांग की कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और भूमि किस उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की जा रही है, उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले से सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिग्रहण के बाद उस भूमि के उपयोग में कोई बदलाव न हो और न ही उसे किसी अन्य पक्ष को लीज पर दिया जाए। किसानों ने यह भी सुझाव दिया कि परियोजना शुरू करने से पूर्व एक समिति गठित की जाए जिसमें किसान, सरकार और डेवलपर सभी शामिल हों और उस समिति के निर्णय के आधार पर ही भूमि पर कोई भी कार्य शुरू किया जाए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में एक और बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया। किसान संघ ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य के अनेक किसान सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण को 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं कर पाए, जिससे वे डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसे सभी किसानों का ब्याज अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री और किसान संघ के बीच यह संवाद न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करने का अवसर बना, बल्कि यह भी दिखा कि सरकार किसान हितों को लेकर गंभीर है। उम्मीद की जा रही है कि इन सुझावों और मांगों के आधार पर सरकार शीघ्र ही भू अधिग्रहण कानूनों में आवश्यक संशोधन कर किसानों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

शराब दुकानों पर पुलिस की सख्त नजर, उज्जैन में 24 घंटे निगरानी और अव्यवस्था पर कड़ी कार्रवाई शुरू

उज्जैन। नगरीय सीमा से बाहर संचालित हो रही शराब दुकानों पर लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायतों के बाद उज्जैन पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर में सामाजिक शांति बनाए रखने और आम नागरिकों को शराब दुकानों से हो रही परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सहायक आबकारी आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब दुकानों की व्यवस्थाओं को तुरंत सुधार और सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर सख्त रोक लगाते हुए इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे और शराब दुकानों का भ्रमण कर उनकी व्यवस्थाओं की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था में बाधा नहीं आनी चाहिए और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब दुकानों के बाहर सार्वजनिक रूप से शराब पीने और यातायात में रुकावट पैदा करने वाले कुल 20 लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त 15 शराब दुकान संचालकों को नियमों का उल्लंघन करने के चलते गिरफ्तार भी किया गया। इस पूरी कार्रवाई के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने आबकारी विभाग को एक आधिकारिक पत्र भेजकर शराब दुकानों की संपूर्ण व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करने और उन्हें नियंत्रित, अनुशासित तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है। पत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शराब दुकानों के बाहर सार्वजनिक रूप से शराब पीने की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि महिलाओं, बच्चों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि इन दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और किसी भी स्थिति में असामाजिक गतिविधियों को पनपने न दिया जाए। शराब दुकानों के बाहर अब सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और किसी भी अनुचित हरकत की तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा हर शराब दुकान पर अब 24 घंटे निगरानी के लिए वालंटियरों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें 6-6 घंटे की शिफ्ट में तैनात किया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से इसीलिए उठाया गया है ताकि दिन और रात किसी भी समय अव्यवस्था या अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने ठेकेदारों को यह भी निर्देशित किया है कि शराब दुकानों के बाहर यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था की जाए और अनावश्यक भीड़भाड़ न होने पाए। यदि किसी दुकान पर अव्यवस्था या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित प्रबंधकों और कर्मचारियों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जिनमें गिरफ्तारी और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

धार में राजस्व टीम पर जानलेवा हमला: सीमांकन से नाखुश किसानों ने पटवारी और कोटवार को बेरहमी से पीटा, महिला आरआई ने भागकर बचाई जान

धार। जिले में बदनावर तहसील के अंतर्गत आने वाले मुलथान गांव में कृषि भूमि के सीमांकन के लिए पहुंचे राजस्व विभाग की टीम पर किसानों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस हमले में पटवारी और कोटवार को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, जबकि महिला राजस्व निरीक्षक किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। हमले में दो किसान भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पटवारी संजय जाट, राजस्व निरीक्षक विनीता पटेल और ग्राम कोटवार सोमेश्वर खेत क्रमांक 571 के सीमांकन के लिए मौके पर पहुंचे थे। नियमानुसार सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की ही जा रही थी कि तभी वहां मौजूद कुछ किसानों ने सीमांकन रुकवाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने टीम से तीखी बहस की और अपने पक्ष में सीमांकन करने का दबाव बनाने लगे। जब राजस्व टीम ने नियम अनुसार कार्य करने की बात कही, तो यह बहस देखते ही देखते उग्र झगड़े में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पांच लोगों ने मिलकर लाठियों से पटवारी संजय जाट और कोटवार सोमेश्वर पर हमला कर दिया। उन्हें दौड़ाकर पीटा गया और बुरी तरह घायल कर दिया गया। महिला आरआई विनीता पटेल किसी तरह घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचा पाईं। स्थिति और अधिक बिगड़ती, उससे पहले कुछ स्थानीय किसानों ने बीचबचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें दो किसान घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एडिशनल एसपी गीतेश गर्ग ने बताया कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी पक्ष सीमांकन अपने मनमाफिक करवाना चाहता था और जब राजस्व टीम ने इसमें कोई समझौता नहीं किया, तो वे हिंसा पर उतर आए। पुलिस ने पटवारी संजय जाट की रिपोर्ट पर पांच लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा करती है। सीमांकन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में लगातार विवाद और हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे न केवल राजस्व अमले की कार्यप्रणाली बाधित हो रही है, बल्कि वे जान जोखिम में डालकर सरकारी काम करने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की पर्याप्त मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, राजस्व कर्मचारियों ने भी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रशासन से स्पष्ट कदम उठाने की अपील की है।

मोदी का नया मंत्र: देरी विकास का दुश्मन...

'देरी, विकास का दुश्मन है' के प्रधानमंत्री के नए मंत्र का ही असर कहा जाएगा कि आर्थिक मोर्चे पर तय लक्ष्यों को हासिल करना आसान हुआ। आर्थिक मोर्चे पर बदलाव का ही असर है कि कुछ ही वर्षों में दुनिया की 11वें नंबर से भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनियाभर की विकास दर को कोरोना की महामारी ने बुरी तरह प्रभावित किया। आज की दुनिया के विकास का ईंधन एक तरह से जैविक ऊर्जा यानी पेट्रोल और डीजल है। अरब देशों के आपसी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को पेट्रोलियम आपूर्ति में बाधा न पड़ना, चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध के बावजूद भारत की विकास दर में कमी ना आना, एक तरह के भारत के संकल्प का नतीजा है। बेशक इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका श्रेय युवाओं को दिया।

उमेश चतुर्वेदी

अमेरिकी लेखक जय एम फिनमैन की अमेरिकी बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर कुछ साल पहले एक पुस्तक आई थी, डिले, डिनाय, डिफेंड...अंग्रेजी के इन तीन शब्दों का अर्थ है टालना, इनकार करना और बचाव करना। इस पुस्तक में फिनमैन ने साबित किया है कि किस तरह बीमा कंपनियां दावों को टालती हैं, देने से इनकार करती हैं और फिर अपने फैसले का बचाव करती हैं। नौकरशाही से जिनका पल्ला पड़ता रहता है, उन्हें भी पता है कि नौकरशाही किस तरह फैसलों को टालती हैं, उनके हिसाब से योजना नहीं हुई तो उससे आगे बढ़ाने से इनकार कर देती है और आखिर में उस योजना का पलीता ही लगा देती है। इस देर और इनकार की कीमत आखिरकार जनता को चुकानी पड़ती है। अव्वल तो तय समय पर लोगों को सहूलियतें मिल ही नहीं पाती। लेकिन जब किसी वजह से परियोजना पर काम चलता भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी लागत खर्च बढ़ चुकी होती है। आखिरकार इसकी कीमत देश को ही चुकानी पड़ती है।

लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र की इस खामी को समझा था। सबसे पहले इस कमजोरी पर काबू पाने की उन्होंने गुजरात में कोशिश की और देश की कमान संभालने के बाद उन्होंने तंत्र से इस खामी को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का यह कहना कि देरी विकास का दुश्मन है और हमारी सरकार इस दुश्मन को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी इसी सोच को जाहिर करता है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं में देरी को देश के विकास की बड़ा रोड़ा बताया है। अपने संबोधन में उन्होंने स्वीकार किया परियोजनाओं में देरी से प्रगति बाधित होती है, जबकि तात्कालिक कार्रवाई से विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में असम के बोगीबील पुल परियोजन का उदाहरण दिया, जिसकी आधारशिला 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रखी थी, बाद में सत्ता संभालते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका काम शुरू कराया। लेकिन बाद की सरकारों के दौरान पता नहीं किन वजहों से इस परियोजना का काम रोक दिया गया। जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश और असम के लाखों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ीं। इस योजना पर दोबारा काम मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ और चार साल में यह पुल बनकर तैयार हुआ और 2018 इसे जनता के लिए खोला गया। अगर इसी हिसाब से देखें तो यह काम 2001 या अधिक से अधिक 2002 में पूरा किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

सत्ताएं बदलते ही कई योजनाएं रोक दी जाती हैं और राजनीतिक नफा-नुकसान को देखते हुए उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। केरल की कोल्लम बाईपास सड़क परियोजना को इसके उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। यह योजना 1972 में शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हुई। तकरीबन पचास साल तक यह योजना लटकी रही। यह बात और है कि इस काम को मोदी सरकार ने ही पूरा किया।

प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या देश के सामने कोई लक्ष्य रखते हैं, तो वे नया नारा भी गढ़ते हैं। 'देरी विकास का दुश्मन है' इस कड़ी में नया नारा है। देश में ऐसी कई परियोजनाएं मिल जाएंगी, जिन्हें तय वक्त तक पूरा नहीं किया जा सका। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर मांझी में एक पुल है। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने इस पुल को केंद्र मे रखकर कविता ही रच डाली है। इस पुल का शिलान्यास जनता पार्टी के शासनकाल के राज्य मंत्री चांद राम ने शुरू किया और दशकों तक इसका काम नहीं हो पाया। अरसे बाद यह पुल बनकर तैयार हो पाया। परियोजनाओं में देरी की ऐसी ढेरों कहानियां पूरे देश में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना का भी इसी संदर्भ में उल्लेख किया है। देश की आर्थिक राजधानी के लिए बेहतर और सुगम हवाई सेवा की जरूरत से किसे इनकार हो सकता है। लेकिन नवी मुंबई में हवाई अड्डा बनाने की चर्चा साल 1997 में शुरू हुई। लेकिन उस परियोजना को ठीक दस साल बाद यानी 2007 में मंजूरी मिल पाई। लेकिन राजनीति और नौकरशाही से कोलाज वाले तंत्र की वजह से इस परियोजना पर ठोस रूप में काम नहीं हो पाया। प्रधानमत्री ने तो सीधे-सीधे इसके लिए इस दौरान केंद्र और महाराष्ट्र में काबिज रही कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री के अनुसार, कांग्रेस की सरकारों ने इस परियोजना में ना तो दिलचस्पी दिखाई, ना ही कोई कार्रवाई नहीं की। यह बात और है कि मोदी सरकार ने इस परियोजना के कामकाज में तेजी लाने की दिशा आगे बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह दूसरी योजनाएं तेज गति से तय वक्त या उससे पहले पूरी हुईं, उसी गति और तेजी से नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना भी पूरा होगी।

देश के आर्थिक विकास की नींव नरसिंह राव ने साल 1991 में रखी थी, जिनके सहयोग से तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की गति को तेज किया था। देश की आर्थिकी को लाइसेंस राज और लालफीताशाही से दूर किया था। उस बदलाव का असर भी दिखा। लेकिन राजकाज की कमान जिस तंत्र के हाथों में रही, वह पुरानी मानसिकता से ग्रस्त रहा। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद इस मानसिकता को थोड़ी लगाम जरूर लगी है। यह बात और है कि इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

'देरी, विकास का दुश्मन है' के प्रधानमंत्री के नए मंत्र का ही असर कहा जाएगा कि आर्थिक मोर्चे पर तय लक्ष्यों को हासिल करना आसान हुआ। आर्थिक मोर्चे पर बदलाव का ही असर है कि कुछ ही वर्षों में दुनिया की 11वें नंबर से भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनियाभर की विकास दर को कोरोना की महामारी ने बुरी तरह प्रभावित किया। आज की दुनिया के विकास का ईंधन एक तरह से जैविक ऊर्जा यानी पेट्रोल और डीजल है। अरब देशों के आपसी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को पेट्रोलियम आपूर्ति में बाधा न पड़ना, चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध के बावजूद भारत की विकास दर में कमी ना आना, एक तरह के भारत के संकल्प का नतीजा है। बेशक इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका श्रेय युवाओं को दिया। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित है। इससे दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। पहले दुनिया मानती थी कि भारत धीरे-धीरे और लगातार प्रगति करेगा, उसी दुनिया को भारत अलग नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो दुनिया अब देश को 'तेज और निडर भारत' के रूप में देख रही है। परियोजनाओं में देरी को विकास के दुश्मन के तौर पर प्रधानमंत्री का स्थापित करना एक तरह से राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को संबोधित करना है। विश्व गुरू बनने की आकांक्षा हो या आर्थिक या दूसरी तरह वैश्विक महाशक्ति बनना, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इसी सोच को हर स्तर पर ना सिर्फ आगे बढ़ाना होगा, बल्कि उसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर भी विकसित किया जाना होगा।

सबको पता है कि कई बार राजनीतिक कारणों से पहले की सरकारों की लाई या उनके द्वारा शुरू या जारी की गई योजनाएं लटका दी जाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कई बार नौकरशाही भी इस डिले, डिनाय और डिस्ट्राय यानी टालना, इनकार करना और खारिज करने के लिए जिम्मेदार होती है। आजादी के पचहतर साल बीतने के बावजूद नौकरशाही में यह मानसिकता बनी हुई है। अब भी तंत्र ऐसे ढेर सारे तत्व हैं, जो योजनाओं को लटकाने और टालने में भरपूर रूचि लेते हैं। एक तरह से ऐसी सोच वाला डीएनए तंत्र में फैला हुआ है। सरकारी तंत्र से जिनका रोजाना पल्ला पड़ता है, अक्सर वे भी फिनमैन जैसी ही सोच रखते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत की सफलता दर अगर बढ़ी है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की दृष्टि है।

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार कौन?

, हर चुनाव के वक्त बन जाती है ऐसी स्थिति

पश्चिम बंगाल में अक्सर कानून व्यवस्था के मसले सियासी बयानबाजियों में उलझा दिए जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि न तो प्रशासन उनसे कोई सबक लेता है और न उसकी जवाबदेही पर आमजन के सवालों के जवाब मिल पाते हैं। मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का हश्र भी वही होता नजर आ रहा है। इस मसले पर विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुट गई हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में वहां आंदोलन शुरू हुआ और बीते शुक्रवार को इसने अचानक हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। उसमें तीन लोग मारे गए और कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

घरों-दुकानों और पुलिस वाहनों में तोड़-फोड़ तथा आगजनी की गई। जब स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो सीमा सुरक्षा बल को बुलाया गया। फिर भी हालात बेकाबू रहे तो बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। स्थिति इस कदर खौफनाक हो गई कि सैकड़ों लोग अपना घर-बार छोड़ कर निकटवर्ती जिले में सुरक्षित जगहों पर पलायन कर गए। भाजपा का आरोप है कि यह हिंसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की वजह से भड़की। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर से लाए गए थे।

हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य होती बताई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मगर यह सवाल अपनी जगह है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार

और प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी स्थिति बन सकती है। खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वे पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होने देंगी।

उन्हें इसके विरोध में उभरने वाले आंदोलन की भी पूरी जानकारी थी। फिर, उन्हें यह अंदाजा कैसे नहीं था कि इसमें दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। अगर वे कह रही हैं कि हिंसा करने वाले बाहर से लाए गए थे, तो हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी वहां के खुफिया तंत्र को कैसे नहीं मिल सकी। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां बाहर से पहुंच गए और कैसे सुरक्षाबलों को इसकी भनक नहीं मिल पाई। इस तर्क के आधार पर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती।

अनेक मौकों पर, सियासी आवेश में, दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को परस्पर भिड़ते देखा गया है। हर चुनाव के वक्त वहां ऐसी स्थिति बन जाती है, सामान्य आंदोलनों के समय भी इसकी आशंका बनी रहती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कुछ इस कदर घुल-मिल गई है कि हर राजनीतिक दल मौका मिलते ही अपने कार्यकर्ताओं को जोर-आजमाइश के लिए ललकारता देखा जाता है।

यह भी छिपी बात नहीं है कि वहां उपद्रवी तत्त्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हर सत्तारूढ़ दल परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने और कानूनी शिकंजे से दूर रखने का भरोसा देता नजर आता है। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में किस कदर राजनीतिक रस्साकशी का माहौल है, वह किसी से छिपा नहीं है। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ऐसी किसी स्थिति से बेखबर कैसे थी और उसने हिंसा रोकने की पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी !

ट्रूक पेश करते हैं अपनी गेमिंग सीरीज़ में बड्स क्रिस्टल डायनो

रु 999 की स्पेशल लॉन्च कीमत पर उपलब्ध

● क्रिस्टल डायनो 21 अप्रैल से एमज़ॉन डॉट इन, फ्लिपकार्ट और ट्रूक डॉट इन पर उपलब्ध होगा ● उपभोक्ता सेल के दिन केवल दो घण्टे के लिए इसे रु 799 की विशेष कीमत पर खरीद सकते हैं, जिसके बाद इसकी कीमत रु.999 होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए विख्यात भारत के सबसे तेज़ी से विकसित होते ऑडियो ब्राण्ड्स में से एक ट्रूक ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई गेमिंग सीरीज़ के लॉन्च की घोषणा की है। बड्स क्रिस्टल डायनो स्लीक चार्जिंग केस, प्रीमियम लैदर फिनिश के साथ भव्य एवं टिकाउ है तथा स्टोरेज एवं चार्जिंग के लिए स्टाइलिश और व्यवहारिक भी है। नया बड्स क्रिस्टल डायनो 21 अप्रैल से एमज़ॉन डॉट इन, फ्लिपकार्ट और ट्रूक डॉट इन पर रु 1099 की कीमत पर खरीद के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि शुरूआती उपभोक्ता मात्र रु 799 की स्पेशल कीमत पर इसे खरीद सकते हैं, यह ऑफर मात्र 2 घण्टे के लिए वैलिड होगा, जिसके बाद इसकी कीमत रु 999 होगी।

तीन आकर्षक रंगों; रैवन ब्लैक, ओक ब्राउन एवं आर्कटिक ब्लू में उपलब्ध बड्स क्रिस्टल डायनो 'मेड इन इंडिया' की अभिव्यक्ति करता है, तथा अपनी शानदार गुणवत्ता के साथ स्थानीय टेक निर्माण को समर्थन प्रदान करता है।

लॉन्च के अवसर पर पंकज उपाध्याय, संस्थापक एवं सीईओ, ट्रूक ने कहा, ''गेमिंग उद्योग लगातार दो अंकों की सालाना दर से विकसित हो रहा है, इसके बावजूद देश के कई टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रीमियम गेमिंग गियर सुलभ नहीं हैं। अपनी नई पेशकश बड्स क्रिस्टल डायनो के साथ हम उच्च गुणवत्ता के बजट अनुकूल ऑडियो समाधान के माध्यम से इस कमी को दूर कर युवा गेमर्स की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। एक ऑडियो ब्राण्ड के रूप में हम गेमर्स की बदलती ज़रूरतों को समझते हैं और उन्हें साउण्ड का ऐसा उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो लुक्स एवं दाम के साथ किसी तरह का समझौता किए बिना गेमप्ले का शानदार अनुभव प्रदान करे। हमें विश्वास है कि यह लॉन्च देश भर के गेमर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, उन्हें उचित कीमत पर बेहतरीन परफोर्मेन्स देगा।

रंजीत टाइम्स

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्ववित्त संस्थान कर्मचारी (गैर शिक्षक) संघ द्वारा कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों के संबंध में दिनांक 16.04.2025 को विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्ववित्त संस्थान कर्मचारी (गैर शिक्षक) संघ के अध्यक्ष दीपक सोलंकी, महासचिव गजेंद्र परमार, उपाध्यक्ष मुकेश गुप्ता एवं जितेंद्र भाटिया, सचिव सोहेल परवेज, मनीष कुमार शर्मा व संतोष मौर्य एवं कोषाध्यक्ष विनय यादव मौजूद रहे। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यगण लोकेश बारूपाल, अब्दुल रज्जाक खान, मुकेश यादव, रामेंद्र सिंह पुंडीर, सत्री देवड़ा, अब्दुल वहाब खान, सचिन वर्मा तथा जितेंद्र पाठक भी उपस्थित थे। 15 दिवस में मांगे न माने जाने की स्थिति में कर्मचारी संघ आंदोलन करने पर विवश होगा जिसकी सूचना ज्ञापन में अंकित है।

ICAI CA इंटर और फाइनल मई परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए इंटरमीडिएट और फाइनल मई सेशन परीक्षा के लिए डमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। लिंक एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट 222.द्बष्द्बद्व.श्वह्द पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी जानकारी जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। आईसीएआई सीए एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम एवं एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जाम माध्यम, ग्रुप इत्यादि जानकारी उपलब्ध होती है।

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 3 से 14 मई तक दो समूहों में देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित होगी। इसकी अवधि 2 घंटे होगी। वहीं सीए फाइनल परीक्षा 2 से 13 मई तक दो समूहों में आयोजित की जाएगी। इसकी अवधि 3 घंटे होगी। दोनों ही परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को उत्तर के लिए हिन्दी या इंग्लिश माध्यम में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में होगा। आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन मई सेशन की तारीख भी घोषित कर दी है। देशभर के विभिन्न शहरों में एग्जाम 15, 17, 19 और 21 मई को आयोजित होगा। एडमिट कार्ड जल्द ही उपलब्ध होंगे। अपडेट्स के लिए नियमित तौर ऑफिसियल वेबसाइट विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है।

इंदौर में मेट्रो रेल के कॉमर्शियल रन को हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना

यात्रियों के लिए मेट्रो चलाने की मेट्रो प्रबंधन की पूरी तैयारी, स्टेशन स्टाफ और टिकट काउंटर बन गए!

इंदौर। इंदौर में मेट्रो रेल की सेवाएं शुरू करने की तैयारी करीब-करीब पूरी हो गई है। लेकिन, इसकी शुरुआत का दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलने पर तय होगा। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर मेट्रो के कॉमर्शियल रन को हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस रन के शुरू होने के दौरान प्रधानमंत्री मौजूद रहे।कोशिश यह भी है कि वे मेट्रो से कुछ दूरी की यात्रा भी करें। बताया जा रहा कि मेट्रो अफसर ने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमे कॉमर्शियल रन शुरू करने की बात कही गई। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेगी और समय तय होने पर आम जनता के लिए मेट्रो की सीमित सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। यात्रियों के लिए मेट्रो चलाने की मेट्रो प्रबंधन की पूरी तैयारी है। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के पांचों मेट्रो स्टेशन पर स्टाफ, टिकट काउंटर सहित अन्य इंतजाम भी हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार चाहेगी तो जल्द ही मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू किया जा सकेगा। सुपर कॉरिडोर पर गांधी नगर से टीसीएस चौराहा तक 6 किमी हिस्से में मेट्रो दौड़ेगी। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 कुल पांच स्टेशन आएंगे। इनमें इलेक्ट्रिकल सेक्शन, प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्कलेटर सहित सभी सुविधाएं जुटाई जा चुकी हैं। ट्रेन को न्यूनतम व अधिकतम गति से चलाकर देखा जा चुका है।

इंदौर में यलो लाइन का प्रायोरिटी रूट कुल 5.9 किमी का है। इसमें 5 स्टेशन रहेंगे। कॉमर्शियल रन के दौरान हर स्टेशन पर मेट्रो सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर पहुंचेगी। अभी पांच स्टेशन मेट्रो डिपो से लेकर सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 के आगे तक टेस्टिंग हो रही है, जो दिन और रात दोनों समय की जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल रन के दौरान जब इस रूट पर मेट्रो चलेगी तो वह हर 2 से 5 मिनट में एक स्टेशन पर पहुंच जाएगी।

इंदौर में गर्मी का कहर : तोड़े रिकॉर्ड, पारा 41 पार, 18 अप्रैल तक तेज गर्मी की चेतावनी

इंदौर। इंदौर शहर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंदौर में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़कर 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, रात का तापमान भी 1.1 डिग्री उछलकर 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में यह बढ़ोतरी गर्मी के प्रकोप को दर्शा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

प्रदेशभर में तेज गर्मी का असर, लू चलने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश में अगले तीन दिनों तक तेज गर्मी का असर बना रहेगा। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में हीट वेव यानी लू चल सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर संभाग में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल तक तेज गर्मी की चेतावनी जारी की है। इस अवधि में बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि पूर्वी मध्यप्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

● तीन वेदर सिस्टम सक्रिय, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर संभव

फिलहाल प्रदेश में मौसम से जुड़े तीन सिस्टम सक्रिय हैं। इनमें दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन शामिल है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 16 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इसका असर मध्यप्रदेश पर दो दिन बाद यानी 18 अप्रैल से दिख सकता है। इससे प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभावित है, जिससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

इंदौर को मिला पूर्वी बायपास का तोहफा, 77 किमी लंबे सिक्स लेन मार्ग का निर्माण नेशनल हाईवे के जिम्मे, 38 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

इंदौर। लंबे समय से अधर में लटके इंदौर के पूर्वी बाईपास प्रोजेक्ट को आखिरकार नई दिशा मिल गई है। कुछ समय पहले इस परियोजना को लोक निर्माण विभाग के जरिए बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सलाह पर इसका जिम्मा दोबारा नेशनल हाईवे को सौंप दिया गया। बीते सप्ताह गडकरी द्वारा देशभर के दस बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया, जिसमें 77 किलोमीटर लंबे और सिक्स लेन वाले इंदौर के पूर्वी बायपास का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसकी अनुमानित लागत 3500 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आगामी दो वर्षों में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछ जाएगा। पूर्वी बायपास प्रोजेक्ट में कुल 38 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें इंदौर के साथ देवास जिले के भी पांच गांव शामिल हैं। इसके समानांतर पश्चिमी बायपास के लिए 31 गांवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि किसानों के विरोध के कारण पश्चिमी बायपास का निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका है। प्रशासन अब गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत कर रहा है और सर्वे भी करवा रहा है, ताकि सहमति प्राप्त कर समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। अहमदाबाद की एक कंपनी को पश्चिमी बायपास के निर्माण का ठेका पहले ही दिया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य शासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बीच हुए एमओयू में इंदौर के पूर्वी बायपास को भी शामिल किया गया था। इससे पहले इस परियोजना को पीडब्ल्यूडी या एमपीआरडीसी से बनवाने की योजना पर काम चल रहा था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह नेशनल हाईवे को सौंप दी गई है।

राज्य सरकार की विकास योजनाओं की कड़ी में अब दूध उत्पादन भी एक प्रमुख लक्ष्य बन चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाकर पांच वर्षों में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य के दुग्ध संघों द्वारा केवल 10 लाख लीटर प्रतिदिन का दुग्ध संकलन किया जाता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देने की घोषणा की है। साथ ही डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना को अधिक प्रचारित कर प्रदेश के दूध को राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी कार्य आरंभ कर दिया गया है।

दूसरी ओर, सागर जिले के 258 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी शासन द्वारा जारी कर दी गई है। इससे वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बल मिलेगा, वहीं पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

प्रदेश में हो रहे इन विकास कार्यों के साथ सड़कों का विस्तार, दूध उत्पादन में वृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने के प्रयास यह संकेत दे रहे हैं कि मध्यप्रदेश तेजी से बदलते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर है।

इन सस्ते और बेहतरीन कोर्स से बना सकते हैं करियर

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कर्मचारियों से कुछ एक्स्ट्रा सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कंपनियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाना शायद किसी के लिए आसान नहीं। इंटरव्यू की बात हो या पहले से ही की जा रही नौकरी में प्रमोशन की हर जगह कुछ एक्स्ट्रा की मांग होती है। यही नहीं अब तो घर में बैठे फ्रीलांस करना हो तो भी लोगों से कई तरह से सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो क्यों न फ्यूचर की प्लानिंग हो जाए। अगर आप आगे चलकर कोई कोर्स करने का सोच रही हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ बेहतरीन कोर्सेस के बारे में।

कई कोर्स आपको घर बैठे कमाने का मौका भी देंगे। चाहें ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा अपने सीवी में दिखाना हो या फिर घर बैठकर काम करना हो, हर जरूरत के हिसाब से एक कोर्स मिल जाएगा। इन सभी कोर्स के जरिए आप नए ट्रेंड के हिसाब से खुद को अपडेट भी कर सकते हैं।

SEO Course

सर्च इंजन ऑपरेशन यानी SEO कोर्स भले ही सुनने में काफी मुश्किल लगता हो पर ये है नहीं। अगर आप थोड़ा भी डिजिटल वर्ल्ड में एक्टिव हैं और गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया आदि के बारे में थोड़ी बेहतर समझ रखती हैं तो ये प्रोफेशनल कोर्स न सिर्फ किसी कंपनी में अच्छी नौकरी दिलवा सकता है बल्कि ये कोर्स आपको बेहतरीन फ्रीलांस का मौका भी दे सकता है। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए। अगर आप नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कई अन्य बड़ी जगहों पर रहती हैं तो 3-6 महीने के कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं। अगर किसी छोटे शहर में रह रही हैं जैसे लखनऊ, भोपाल आदि तो भी वहां कई इंस्टिट्यूट ऐसे हैं जो ये कोर्स ऑनलाइन भी करवाते हैं। इसमें भी अलग-अलग तरह के कोर्स हो सकते हैं जैसे मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कीवर्ड प्लानर आदि सब कुछ। इनमें से कुछ फ्रीलांस और कुछ कंपनियों के लिए बेहतर होते हैं।

फीस - इस कोर्स की फीस जगह के हिसाब से बदल सकती है। ये 7000 रुपए से शुरू होकर 25000 तक जा सकती है।

PPC Course

ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें फ्रीलांस करना है। इसका मतलब है Pay Per Click, जिसमें सेल्स का काम होता है। सर्च इंजन की मदद से आप पेड एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। आजकल लगभग हर बिजनेस इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रांड को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए PPC कोर्स या गूगल एडवर्ड कोर्स के नाम से अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुन सकती हैं आप।

फीस - इसकी फीस 15000 से शुरू हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से शहर में रहती हैं।

Content Writing Course

फ्रीलांसिंग के लिए सबसे अच्छे कुछ कोर्स में से एक है कंटेंट राइटिंग कोर्स। अगर आपको लिखने का शौख है तो आप अपने पैशन को करियर भी बना सकती हैं। इसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग ही नहीं बल्कि फुल टाइम जॉब के भी बहुत विकल्प होते हैं। साथ ही, कई मीडिया हाउस बेहतरीन मौका दे सकते हैं। यही नहीं अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छी हैं तो आपके लिए कई तरह से मुमकिन है कि न सिर्फ मीडिया हाउस में बल्कि आप कई कंपनियों में फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं।

फीस - कंटेंट राइटिंग के लिए वीकएंड क्लास और वीकडे क्लास दोनों वाला कोर्स उपलब्ध है। इसकी फीस भी 8000 रुपए से शुरू हो सकती है।

Makeup Course

मेकअप का मतलब यहां रोजमर्रा के लिए सज कर जाना या ब्यूटीपार्लर के सेल्फ कोर्स से नहीं है। यहां बात हो रही है प्रोफेशनल मेकअप इंस्टिट्यूट से कोर्स करने की। इसमें ब्राइडल मेकअप, एयरब्रश मेकअप आदि के कोर्स उपलब्ध हैं। कई एप्स जैसे अर्बनक्लैप आदि ऐसे प्रोफेशनल्स को बहुत बेहतरीन मौका देते हैं और महीने का 1.5 लाख तक कमाया जा सकता है। पर शर्त ये है कि ये कोर्स प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट से किया गया हो।

फीस - इस कोर्स की फीस आपकी जरूरत के हिसाब से हो सकती है। इसकी कीमत 15000 रुपए से शुरू होती है, लेकिन अगर इंस्टिट्यूट काफी अच्छा है तो ये महंगा भी साबित हो सकता है।

Nail Art Course

ये शॉर्ट टर्म कोर्स है और अगर आपने ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाने का सोच लिया है तो फिर नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन कोर्स एक ट्रेंडी विकल्प साबित हो सकता है। ये काफी डिमांड में है और कई सारे ब्यूटी इंस्टिट्यूट प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें सिर्फ नेल आर्ट ही नहीं बल्कि नाखूनों से जुड़ी बीमारियों आदि की जानकारी भी दी जाएगी।

फीस - इस कोर्स की फीस 3000 रुपए से शुरू हो सकती है।

अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपना कोर्स चुन सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जिस भी इंस्टिट्यूट को चुनें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। सर्टिफिकेशन कोर्स ही बेहतर होते हैं इसलिए बिना सर्टिफिकेट वाला कोई कोर्स न चुनें।

कम समय में चाहते हैं शानदार करियर ग्रोथ? तो लाइफस्टाइल में शामिल करें ये 4 आदतें

करियर में करना चाहती हैं ग्रोथ? लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ पा रही हैं आगे, तो चलिए हम आपको यहां बताते हैं कि इसके लिए आपको अपनी किन आदतों में बदलाव करना चाहिए।

करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कुछ लोग सफल व्यक्ति को देखकर ये सोच लेते हैं कि उनके साथ शायद वह समस्या नहीं रही होगी, जिन परेशानियों से मैं गुजर रही हूं। पर, ये सोच ही गलत है क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह होती है। हर किसी को परिश्रम और संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है। सफल लोग के पास भी हफ्ते के 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि ऐसे लोग अपनी लाइफस्टाइल को लेकर काफी सख्त होते हैं और हर चीज को एक रूटीन के हिसाब से करते हैं। अगर आप भी करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको भी अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आदतों को शामिल कर लेना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आइए हम आपको यहां 4 आदतों के बारे में बताते हैं, उनमें सुधार लाने के बाद आप काफी आगे बढ़ सकते हैं।

टालमटोल की आदत बदलें

हर काम के लिए एक समय तय करना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर सेल्फ डिसिप्लिन होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हर छोटे-बड़े काम को टालते रहेंगे, तो यह भविष्य के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। बेहतर यही होगा कि टालने की आदत को बदलें और आप अपने काम का समय रहते पूरा कर लें।

लक्ष्य बनाकर करें काम

अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोलतय करने की आदत डालें। इससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। ये हैबिट आपके काम के स्पीड और समझ में तेजी ला सकता है। साथ ही, आपका दिमाग भी इससे खुलेगा, जिससे आपको जॉब में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाएंगे।

दूसरे पर न रहें निर्भर

करियर में सही मुकाम हासिल करने के लिए स्वयं कुछ नियम-कायदे बनाना और उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी योग्यता के अनुसार, खुद को समझना होगा और बेहतर करने के लिए निर्णय खुद लेने की आदत डालनी होगी। अगर आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है।

नई चीजें सीखने की डालें आदत

अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, आपको लगातार नई चीजें सीखते रहना होगा। अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और विकासों से अपडेट रहें। नए कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यशालाओं में भाग लें। आपकी नॉलेज आपकी ग्रोथ में काम आ सकते हैं।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव: केंद्रीय पैनल के 4 पदों के लिए 165 नामांकन

अध्यक्ष पद के 48 दावेदार

नईदिल्ली, एजेंसी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव का काउंटडाउन तेज हो गया है। जेएनयू में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन हुआ। सबसे अधिक अध्यक्ष पद पर 48 छात्रों ने नामांकन किया। नामांकन वापस लेने की बुधवार को अंतिम तिथि है। जेएनयूएसयू चुनाव 25 अप्रैल को कराए जाएंगे और 28 अप्रैल को नतीजों की घोषणा की जाएगी।

जेएनयूएसयू चुनाव समिति को केंद्रीय पैनल के चार पदों के लिए 160 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं, जबकि 16 स्कूलों में 'स्कूल काउंसलर' पदों के लिए 250 छात्रों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। चुनाव समिति के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए 48, उपाध्यक्ष पद के लिए 41, महासचिव पद के लिए 42 और संयुक्त सचिव पद के लिए 34 नामांकन प्राप्त हुए। इस तरह, केंद्रीय पैनल के लिए 165 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव लिए नामांकन पत्र

दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि बुधवार है। इसके बाद दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 17 और 21 अप्रैल को स्कूल स्तर पर 'जनरल बॉडी मीटिंग' (जीबीएम) होंगी। विश्वविद्यालय-व्यापी जीबीएम के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया है, जबकि अध्यक्ष पद के लिए होने वाली बहस 23 अप्रैल को होगी। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। 25 अप्रैल को दो सत्रों में मतदान होगा। पहले सत्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरे सत्र में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। उसी रात 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और अंतिम नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे।

जेएनयूएसयू चुनाव समिति द्वारा रविवार 13 अप्रैल को जारी की गई वोटर लिस्ट के अनुसार इस साल आगामी चुनाव में 7906 छात्र वोट डालने के पात्र हैं। मतदाता आंकड़ों के अनुसार, पंजीकृत मतदाताओं में से 43 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि शेष पुरुष हैं। गौरतलब है कि, पिछले साल जेएनयूएसयू चुनाव चार साल के अंतराल के बाद 22 मार्च, 2024 को हुए थे। यूनाइटेड लेफ्ट गठबंधन ने चार केंद्रीय पैनल पदों में से तीन पर जीत हासिल की थी, जबकि बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संघ ने चौथा स्थान हासिल किया।

दिन भर कैंपस में छात्रों ने अपने अपने संगठनों के लिए कैंपेनिंग की। बहुत संभावना है कि इस बार भी वाम संगठन छात्र संघ चुनाव में मिलकर लड़ें। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने संभावित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एबीवीपी की ओर से इस बार थीटे शांभवी प्रमोद,अनुज दमाड़ा, कुणाल राय, विकाश पटेल, राजेश्वर कांत दुबे, शिखा स्वराज, निट्टू गौतम, अरुण श्रीवास्तव तथा आकाश कुमार रवानी मैदान में हैं। इन सभी संभावित प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन्हीं नामों में से जेएनयूएसयू सेन्ट्रल पैनल के लिए चार नाम तय होंगे। एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन कैंपस के मुद्दों के साथ छात्रों से मिल रहे हैं।

सीबीआई ने दिल्ली के अस्पताल में दवा घोटाले का केस दर्ज करने की मांगी इजाजत

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में हुए कथित दवा घोटाले की शिकायत पर सीबीआई ने जांच के बाद केस दर्ज करने के लिए दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी है।

दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) भी इस अस्पताल में हुए दवा घोटाले के मामले की जांच कर रही है। सरकार की इजाजत मिलने के बाद सीबीआई मामले की जांच करेगी। गत जनवरी में दवा घोटाले को लेकर विजिलेंस को शिकायत की गई थी।

बिना टेंडर जारी किए दवा खरीदी : विजिलेंस को दी गई शिकायत में बताया गया था कि मेरठ से संचालित एक निजी कंपनी ने अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई की थी। आरोप है कि इस कंपनी से दवा मंगवाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं किया। अस्पताल प्रशासन ने वैध टेंडर जारी किए बिना कंपनी को दवा का ऑर्डर दिया था। उसके बाद कंपनी के सारे बिल पास कर भुगतान कर दिया गया। यह न केवल प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन था, बल्कि दवा की खरीद के लिए स्वीकृति देने वाली संस्था के नियमों का भी उल्लंघन था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू की तो गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अस्पताल प्रशासन और अन्य एजेंसियों को पत्र जारी किए गए। सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद घोटाले की जांच शुरू करने और केस दर्ज करने की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार को 10 मार्च को पत्र लिखा है। इस दौरान दिल्ली में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया।

एयर होस्टेस के साथ हुआ था गंदा काम,अब मेदांता अस्पताल ने खुद जारी किया बयान

नईदिल्ली, एजेंसी। गुरुग्राम में 46 साल की एयर होस्टेस के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले पर अब अस्पताल का बयान सामने आया है। मेदांता अस्पताल ने अपने परिसर के अंदर हुए इस मामले पर कहा कि उसने सभी सीसीटीवी फुटेज और जरूरी जानकारी पुलिस के साथ साझा कर दी हैं। अस्पताल का कहना है कि अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। बता दें कि यह घटना तब हुई,जब महिला वेंटिलेटर पर थी।

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने पूरे मसले पर आज बयान जारी कर कहा कि हमें एक मरीज से शिकायत मिली है और हम संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। इस स्तर पर,कोई भी आरोप सही साबित नहीं हुआ है और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं।

मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि एक 46 वर्षीय एयर होस्टेस ने शिकायत दर्ज कराई है कि 6 अप्रैल को जब वह वेंटिलेटर पर थीं,तब गुरुग्राम के एक अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अपनी पुलिस शिकायत के अनुसार,वह कंपनी की ओर से ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम आई थीं। इसी दौरान डूबने की घटना के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई,जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस टीम जल्द ही आरोपी की पहचान कर मामले के नियमों के अनुसार उसे गिरफ्तार करेगी। मामले की जांच जारी है।

मकान रिलीज करवा दीजिए, दिल्ली पुलिस को दें आदेश; जिस फ्लैट में हुआ था श्रद्धा वॉकर का मर्डर उसका मालिक पहुंचा कोर्ट

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के महरौली स्थित जिस फ्लैट में तीन साल पहले आफताब पूनावाला ने अपनी लिवइन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या करके उसके टुकड़े-टुकड़े किए थे, उसके मालिक ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अदालत ने गुरुवार को मकान मालिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने दिल्ली पुलिस को अपने मकान को रिलीज (मुक्त) कराने का आदेश देने की मांग की है।

इस महीने की शुरुआत में साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत में दायर आवेदन में मकान मालिक ने दलील दी है कि उसकी प्रॉपर्टी- महरौली के छतरपुर पहाड़ी में पहली मंजिल का फ्लैट, पुलिस के कब्जे से उसे वापस सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और ट्रायल अंतिम चरण में है। उनके अनुसार, फ्लैट के सभी भौतिक साक्ष्य और तस्वीरें पहले से ही केस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर फ्लैट का कब्जा मकान मालिक को वापस सौंप दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस ने जवाब में कहा कि

सीआरपीसी की धारा 310 के तहत अदालत द्वारा फ्लैट का स्थानीय निरीक्षण करने की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए सबूत रिकॉर्ड करने से पहले परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 310 जज या मजिस्ट्रेट को किसी मामले की सुनवाई के दौरान पेश सबूतों को समझने के लिए उस स्थान का दौरा करने और निरीक्षण करने की अनुमति देती है, जहां कथित अपराध हुआ था। 18 मई 2022 को, 28 साल के प्रशिक्षित शेफ आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी और उसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद पूनावाला ने वॉकर के शरीर के अंगों को कुछ दिनों तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और फिर अगले 18 दिनों तक छतरपुर के जंगल में फेंकता रहा। 12 नवंबर, 2022 को दिल्ली पुलिस ने आफताब को तब गिरफ्तार किया, जब उसके बयान में विसंगतियां मिलीं। केस सामने आने के बाद से ही छतरपुर का फ्लैट बंद है और केस रिकॉर्ड का हिस्सा है।

मकान मालिक ने याचिका में कहा है कि फ्लैट पिछले एक साल से अधिक समय से पुलिस की हिरासत में है और इसकी मरम्मत की जरूरत है। फ्लैट के केस प्रॉपर्टी बनने के कारण उसे किराये की आय का नुकसान हो रहा है। आवेदन में कहा गया है कि उसने 16 मई 2022 को आरोपी आफताब पूनावाला और मृतक श्रद्धा वॉकर को फ्लैट किराए पर दिया था। घटना के बाद महरौली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जांच के मकसद से फ्लैट को बंद कर दिया था और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। आवेदन में कहा गया है, मामले की सुनवाई समाप्त होने तक अनिश्चित अवधि के लिए संपत्ति को अपने पास रखना सही और न्याय हित में नहीं है।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल पर चार्जशीट को लेकर भड़की कांग्रेस, देशभर में ई डी ऑफिस के बाहर हल्लाबोल

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल पर चार्जशीट को लेकर भड़की कांग्रेस ने ई डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देशभर में ई डी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्त्ता प्रदर्शन कर रहे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम है।

25 अप्रैल को सुनवाई

इसके विरोध में आज कांग्रेस देशभर के ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी।

क्या है ई डी का आरोप

ई डी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एक निजी कंपनी 'यंग इंडियन' के ज़रिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को सिर्फ़ 50 लाख रुपये में हथियाने की साजिश रची। इस कंपनी के 76 फ़ीसदी शेयर सोनिया और राहुल के पास हैं। इस मामले में 'अपराध से अर्जित आय' 988 करोड़ रुपये मानी गई। साथ ही, संबंधित संपत्तियों का बाज़ार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस - भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी।